

अनुभव

जिम्मेदारी

हजारों सफलताओं की एक पहचान

ध्येय IAS...

अब नये प्रारूप में

IAS/PCS परीक्षाओं की मांग के अनुरूप

महत्वपूर्ण लेख विश्लेषण

Date:- 24-03-2026

INDEX

Sr. No.	Editorial	Source	Page No.
1	Surplus heat is the new climate challenge	The Indian Express	02-11
2.	As West Asia war continues, the zone of uncertainty expands each day	The Indian Express	12-21
3.	UGC needs reform. But the new higher education bill is not the answer	The Indian Express	22-31
4.	Science and the power of jan bhagidari can lead to a TB-free India	The Indian Express	32-42
5.	Grim future: On the economy, discomfitting data	The Hindu	43-53
6.	Delimitation after 2027, redrawing power in India	The Hindu	54-63

TO GET FREE ACADEMIC SUPPORT

SCAN THIS QR CODE & JOIN



(Scan with Google Lens)

PRAYAGRAJ: II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil, Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068

ALIGANJ: A-12 Sector-J Aliganj, Lucknow (UP). Ph : 0522-4045320, 7619903300

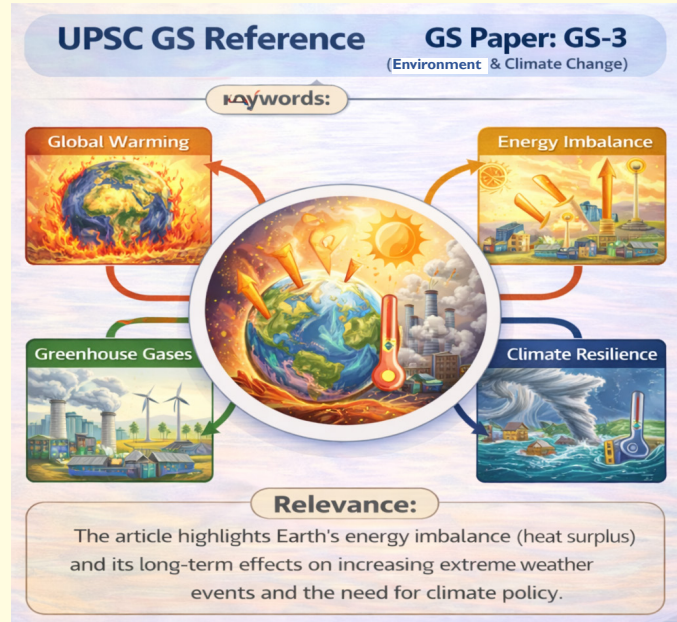
GOMTI NAGAR: CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5 Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar Lucknow-226010 (UP). Ph: 7234000501, 7570009003

1 Surplus heat is the new climate challenge

❖ लेख का दृष्टिकोण:

सरकारों को दीर्घकालिक और राजनीतिक दबाव से मुक्त स्थिर जलवायु नीतियाँ बनानी चाहिए क्योंकि पृथ्वी में जमा अतिरिक्त ऊष्मा आने वाले दशकों तक जलवायु संकट को बढ़ाएगी।

❖ **Author: Editorial**



Article Summary

भूमिका

हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन केवल तापमान वृद्धि तक सीमित नहीं रहा बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली के असंतुलन के रूप में उभर रहा है। World Meteorological Organization की नवीनतम State of Climate Report के अनुसार पिछले दस वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म दशक रहे हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 50 प्रतिशत बढ़ चुकी है। इसके कारण पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में असंतुलन पैदा हुआ है, जिससे अतिरिक्त ऊष्मा वातावरण और महासागरों में जमा हो रही है।

यह 'heat surplus' आने वाले दशकों तक जलवायु प्रणाली को प्रभावित करेगा और extreme weather घटनाओं की आवृत्ति तथा तीव्रता बढ़ाएगा।

मुख्य भाग

पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली का संतुलन बिगड़ चुका है। सामान्यतः सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से अंतरिक्ष में लौटने वाली ऊर्जा लगभग बराबर होनी चाहिए। किंतु ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ने इस संतुलन को बाधित कर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले छह दशकों में पृथ्वी में अतिरिक्त ऊष्मा का संचय हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भले ही आज ही वैश्विक उत्सर्जन शून्य हो जाए, फिर भी पहले से जमा ऊर्जा के कारण ग्रह का तापमान आगे भी बढ़ता रहेगा। इस प्रकार जलवायु संकट केवल उत्सर्जन का नहीं बल्कि ऊर्जा असंतुलन का संकट बन चुका है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू महासागरों की भूमिका है। पानी में ऊष्मा को संग्रहित करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए महासागर अतिरिक्त ऊर्जा के मुख्य भंडार बन गए हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से कई प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, गर्म महासागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी की परावर्तन क्षमता (albedo) कम हो रही है। जब बर्फ पिघलती है तो सूर्य की ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करने की क्षमता घट जाती है, जिससे ऊर्जा असंतुलन और अधिक बढ़ जाता है।

जलवायु संकट: ऊर्जा असंतुलन



ऊर्जा संतुलन

सूर्य से आने वाली ऊर्जा और पृथ्वी से लौटने वाली ऊर्जा बराबर



ग्रीनहाउस गैसों

ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ऊर्जा को फंसाती है



ऊष्मा संचय

पृथ्वी में अतिरिक्त ऊष्मा का संचय होता है



महासागरों की भूमिका

महासागर अतिरिक्त ऊर्जा के मुख्य भंडार बन जाते हैं



बर्फ का पिघलना

ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से परावर्तन क्षमता कम हो जाती है



ऊर्जा असंतुलन

ग्रह का तापमान आगे भी बढ़ता रहेगा

तीसरा पहलू यह है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल छोटे-मोटे सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। वर्तमान नीतियाँ प्रायः ऊर्जा उत्पादन को हरित बनाने पर केंद्रित हैं। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार हुआ है, फिर भी वैश्विक ऊर्जा मांग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कुल उत्सर्जन अभी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रहा है। इसलिए केवल ऊर्जा परिवर्तन ही पर्याप्त नहीं होगा; समाज को जलवायु प्रभावों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता भी है। इसमें जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना और कमजोर समुदायों की सुरक्षा शामिल है।

अंततः यह एक दीर्घकालिक नीति चुनौती भी है। ऊर्जा असंतुलन के प्रभाव कई दशकों तक सामने आते रहेंगे, इसलिए जलवायु नीतियाँ भी दीर्घकालिक दृष्टि से स्थिर होनी चाहिए। यदि नीतियाँ बार-बार बदलती रहेंगी तो निवेश, अनुसंधान और तकनीकी विकास बाधित होंगे। इसलिए सरकारों को ऐसी संस्थागत व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो जलवायु नीति को अल्पकालिक राजनीति से अलग रख सके। स्थिर नीति ढाँचा ही ऊर्जा परिवर्तन, हरित तकनीक और जलवायु अनुकूलन के लिए आवश्यक निवेश को आकर्षित कर सकता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण



निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के मौजूदा चरण में सबसे बड़ी चुनौती केवल उत्सर्जन कम करना नहीं बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में पैदा हुए असंतुलन को समझना और उसके प्रभावों के लिए तैयार होना है। अतिरिक्त ऊष्मा का संचय आने वाले दशकों तक महासागरों, मौसम प्रणालियों और पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित करता रहेगा। इसलिए सरकारों को एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी जिसमें उत्सर्जन में कमी, अनुकूलन उपाय और जलवायु-सहिष्णु विकास शामिल हों। लेखक का मुख्य संदेश स्पष्ट है कि जलवायु नीति को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर उठाकर दीर्घकालिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लागू करना आवश्यक है। केवल स्थिर, दीर्घकालिक और वैज्ञानिक रूप से आधारित नीतियाँ ही पृथ्वी को बढ़ते जलवायु संकट से बचाने में सहायक हो सकती हैं।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> • Context : पृथ्वी में ऊर्जा असंतुलन बढ़ रहा है • Core claim : Heat surplus भविष्य की जलवायु चुनौती है • Reason-1 : ग्रीनहाउस गैसों से ऊर्जा संतुलन बिगड़ा • Reason-2 : महासागर अतिरिक्त ऊष्मा के भंडार बन गए • Trade-off : केवल incremental climate action पर्याप्त नहीं • Way forward : दीर्घकालिक स्थिर जलवायु नीतियाँ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. पिछले दशक को इतिहास का सबसे गर्म दशक बताया गया। 2. वातावरण में CO₂ स्तर pre-industrial स्तर से लगभग 50% अधिक हो गया है। 3. महासागर अतिरिक्त ऊष्मा के मुख्य भंडार बन गए हैं जिससे मजबूत चक्रवात और समुद्र स्तर वृद्धि हो रही है।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार से जलवायु संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। किंतु लेखक का तर्क है कि ऊर्जा मांग में तेज वृद्धि और पहले से जमा ऊष्मा के कारण केवल ऊर्जा परिवर्तन पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ अनुकूलन और लचीले बुनियादी ढाँचे पर समान ध्यान देना आवश्यक है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Planetary Energy Imbalance concept Ocean heat content as climate indicator Climate-resilient infrastructure Early warning systems for disasters 	<ol style="list-style-type: none"> Energy Imbalance <ul style="list-style-type: none"> पृथ्वी में आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच अंतर। Example: GHG के कारण heat trapping बढ़ना। Greenhouse Gases <ul style="list-style-type: none"> ऐसी गैसों जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोकती हैं। Example: CO₂, Methane. Ocean Heat Content <ul style="list-style-type: none"> महासागरों में संग्रहित कुल ऊष्मा की मात्रा। Example: Warm oceans → stronger cyclones. Climate Resilience <ul style="list-style-type: none"> जलवायु प्रभावों से निपटने और अनुकूलन की क्षमता। Example: Flood-resilient infrastructure.

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> • Long-term climate policy frameworks • Climate governance insulated from politics 	<p>5. Early Warning System</p> <ul style="list-style-type: none"> • आपदाओं के पहले चेतावनी देने वाली तकनीकी प्रणाली। • Example: Cyclone alerts by meteorological agencies.

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:-1

Climate change is increasingly being driven by the Earth's energy imbalance rather than merely rising emissions. Discuss its implications for global climate policy.

Keywords: Energy imbalance, greenhouse gases, ocean heat, extreme weather, climate adaptation, mitigation, resilience, climate governance

Model Answer Draft

Introduction:

जलवायु परिवर्तन पर पारंपरिक चर्चा प्रायः ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर केंद्रित रही है। किंतु हालिया वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में असंतुलन, जिसमें ग्रह में अतिरिक्त ऊष्मा का संचय हो रहा है, जलवायु संकट का नया आयाम बन गया है। यह असंतुलन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित कर रहा है।

Body:

ऊर्जा असंतुलन का मुख्य कारण ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है, जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को रोकती है। परिणामस्वरूप अतिरिक्त ऊर्जा वायुमंडल और महासागरों में जमा हो जाती है। महासागर इस अतिरिक्त ऊष्मा के सबसे बड़े भंडार बन चुके हैं, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता बढ़ रही है। इसके अलावा ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि और पृथ्वी की परावर्तन क्षमता में कमी आती है, जिससे ऊर्जा असंतुलन और बढ़ जाता है।

यह स्थिति वैश्विक जलवायु नीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती है। केवल उत्सर्जन कम करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि पहले से जमा ऊष्मा आने वाले दशकों तक प्रभाव डालती रहेगी। इसलिए नीति ढाँचे में अनुकूलन उपायों को भी प्रमुख स्थान देना होगा। इसमें जलवायु-सहिष्णु बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना और संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा शामिल है।

Conclusion:

अतः जलवायु नीति को केवल उत्सर्जन नियंत्रण तक सीमित न रखकर ऊर्जा असंतुलन के दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। स्थिर, विज्ञान आधारित और दीर्घकालिक नीतियाँ ही वैश्विक जलवायु संकट का प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती हैं।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Energy imbalance concept • Ocean heat role • Mitigation + adaptation balance 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल emissions reduction तक सीमित जवाब • adaptation dimension भूल जाना

प्रश्न:-1

“Incremental climate actions are insufficient to tackle extreme weather events.” Examine in the context of contemporary climate governance.

Keywords: Extreme weather, resilience, adaptation, climate infrastructure, early warning, climate governance

Model Answer Draft

Introduction:

वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़, चक्रवात, हीटवेव और सूखा जैसी चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति संकेत देती है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पहले से अधिक जटिल और व्यापक हो चुके हैं।

Body:

Incremental climate actions, जैसे सीमित उत्सर्जन कटौती या आंशिक ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु संकट के पैमाने की तुलना में अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण पृथ्वी की ऊर्जा प्रणाली में दीर्घकालिक असंतुलन है। महासागर और वातावरण में जमा अतिरिक्त ऊष्मा मौसम प्रणालियों को अधिक अस्थिर बना रही है, जिससे चक्रवात और हीटवेव अधिक तीव्र हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर भी पड़ता है। कमजोर समुदाय, तटीय क्षेत्र और कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएँ

विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। इसलिए जलवायु शासन में केवल शमन (mitigation) ही नहीं बल्कि अनुकूलन (adaptation) और लचीलापन (resilience) पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

सरकारों को जलवायु-सहिष्णु बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विस्तार और दीर्घकालिक निवेश रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए। इसके साथ ही जलवायु नीति को अल्पकालिक राजनीतिक हितों से अलग रखते हुए स्थिर नीति ढाँचा तैयार करना आवश्यक है।

Conclusion:

इस प्रकार स्पष्ट है कि जलवायु संकट का सामना करने के लिए व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हैं। केवल छोटे-छोटे सुधारों से समस्या का समाधान संभव नहीं है; बल्कि दीर्घकालिक, बहुस्तरीय और समन्वित जलवायु शासन ही extreme weather चुनौतियों का प्रभावी उत्तर दे सकता है।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> Resilience concept Climate governance reforms Infrastructure adaptation 	<ul style="list-style-type: none"> Extreme weather को climate change से न जोड़ना Concrete policy solutions न देना

Case Study

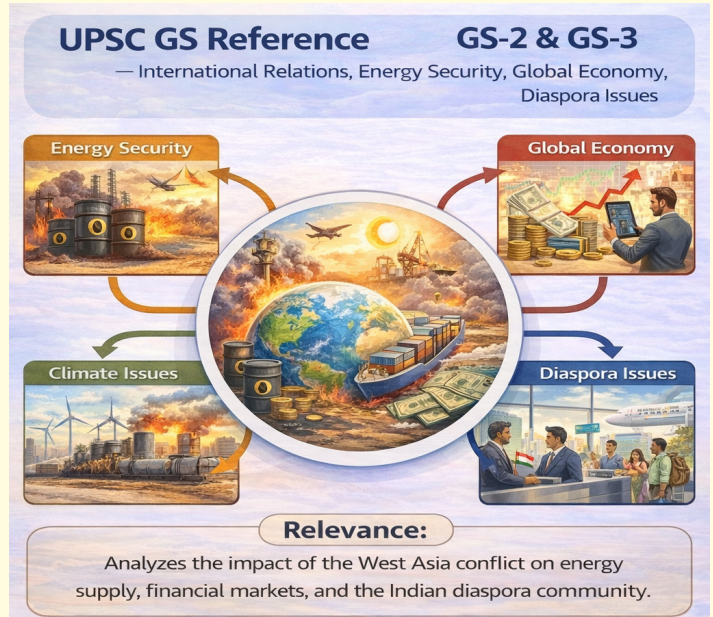
1. **Paris Agreement** - वैश्विक उत्सर्जन नियंत्रण प्रयास
2. India's National Mission on Sustainable Habitat
3. UN Early Warning for All Initiative

2 As West Asia war continues, the zone of uncertainty expands each day

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेखक का तर्क है कि West Asia युद्ध के कारण बढ़ती अनिश्चितता से निपटने के लिए भारत को आर्थिक, ऊर्जा और नीति स्तर पर आंतरिक समायोजन करना होगा।

❖ Author: Editorial



Article Summary

भूमिका

पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए इसका प्रभाव और भी अधिक है। हाल ही में लोकसभा में दिए गए अपने संबोधन में Narendra Modi ने इस संकट की तुलना कोविड-19 जैसी चुनौती से करते हुए राष्ट्रीय एकजुटता और तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया। इस संघर्ष ने न केवल ऊर्जा आपूर्ति को बाधित किया है बल्कि वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखलाओं

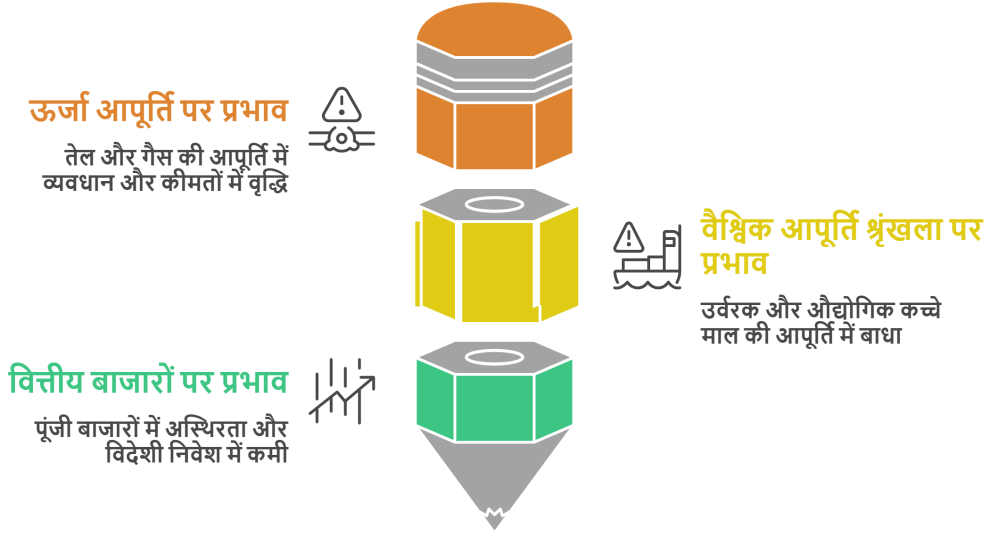
में व्यवधान और भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को भी जन्म दिया है। परिणामस्वरूप भारत को इस बढ़ती अनिश्चितता से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक समायोजन की आवश्यकता होगी।

मुख्य भाग

सबसे पहले, यह संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है। पश्चिम एशिया विश्व के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आयात करता है। जब क्षेत्र में युद्ध या राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो तेल और गैस की आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो जाता है, जिससे कीमतों में तेजी आती है। इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर कई स्तरों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, परिवहन और बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई का दबाव बढ़ता है। इससे आर्थिक विकास दर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस संघर्ष का प्रभाव केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस क्षेत्र से उर्वरक और औद्योगिक कच्चे माल जैसे सल्फर और अमोनिया की बड़ी मात्रा निर्यात होती है। इन वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से कृषि और औद्योगिक उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उर्वरक की कमी कृषि लागत को बढ़ा सकती है और खाद्य सुरक्षा पर दबाव डाल सकती है। इसी प्रकार कई उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन में गिरावट आ सकती है।

पश्चिम एशिया संघर्ष का प्रभाव



तीसरा, इस संघर्ष का प्रभाव वित्तीय बाजारों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। युद्ध के कारण वैश्विक निवेशक जोखिम से बचने की रणनीति अपनाते हैं, जिससे पूंजी बाजारों में अस्थिरता बढ़ जाती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी इसका उदाहरण है। रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने मार्च में अरबों डॉलर की निकासी की है और भारतीय मुद्रा पर भी दबाव बढ़ा है। इससे विनिमय दर में गिरावट और आयात लागत में वृद्धि हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में लगभग एक करोड़ भारतीय प्रवासी रहते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा और संभावित निकासी भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय और रणनीतिक आयाम भी रखता है। इसलिए भारत को अपनी विदेश नीति, ऊर्जा रणनीति और आर्थिक नीतियों में समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

पश्चिम एशिया में संघर्ष



निष्कर्ष

पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष वैश्विक व्यवस्था की जटिलता और परस्पर निर्भरता को उजागर करता है। ऊर्जा आपूर्ति, वित्तीय बाजार, आपूर्ति श्रृंखला और प्रवासी समुदाय जैसे कई क्षेत्र इस संकट से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए भारत को केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि दीर्घकालिक रणनीति

अपनानी चाहिए। इसमें ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक भंडार का निर्माण, आर्थिक लचीलापन और प्रभावी कूटनीति शामिल हैं। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि बढ़ती अनिश्चितता के इस दौर में सरकार, उद्योग और समाज सभी को संभावित लागतों के लिए तैयार रहना होगा और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से इस संकट का सामना करना होगा।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : West Asia युद्ध से वैश्विक अनिश्चितता ● Core claim : भारत को आर्थिक और नीति स्तर पर समायोजन करना होगा ● Reason-1 : ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर प्रभाव ● Reason-2 : आपूर्ति श्रृंखला और वित्तीय बाजार अस्थिरता ● Trade-off : आर्थिक लागत बनाम रणनीतिक सुरक्षा ● Way forward : ऊर्जा विविधीकरण और आर्थिक लचीलापन 	<ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय शेयर बाजार 2.46% गिरा और संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 10% गिरावट दर्ज हुई। 2. विदेशी निवेशकों ने मार्च में \$11.8 billion की निकासी की। 3. भारत के LNG आयात का 41.4% कतर से आता है।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में विविधता और वैकल्पिक स्रोतों के कारण किसी एक क्षेत्र का संकट दीर्घकालिक प्रभाव नहीं डाल पाएगा। किंतु लेखक का तर्क है कि पश्चिम एशिया वैश्विक ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला का

केंद्रीय क्षेत्र है। इसलिए वहां का संघर्ष व्यापक आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जिससे भारत जैसे देशों को दीर्घकालिक नीति समायोजन करना आवश्यक हो जाता है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> • Energy import dependency of India 	<p>1. Energy Security</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऊर्जा की स्थिर और सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करना। • Example: भारत द्वारा तेल आयात स्रोतों का विविधीकरण।
<ul style="list-style-type: none"> • Strategic Petroleum Reserve concept 	<p>2. Supply Chain Disruption</p> <ul style="list-style-type: none"> • उत्पादन और वितरण नेटवर्क में व्यवधान। • Example: युद्ध के कारण उर्वरक निर्यात में कमी।
<ul style="list-style-type: none"> • Diaspora diplomacy 	<p>3. Capital Outflow</p> <ul style="list-style-type: none"> • विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी। • Example: संकट के समय शेयर बाजार से विदेशी निवेश का बाहर जाना।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> • Supply chain vulnerabilities • Financial market volatility • Energy diversification strategy 	<p>4. Strategic Petroleum Reserve</p> <ul style="list-style-type: none"> • तेल की आपूर्ति संकट से निपटने के लिए सरकारी भंडार। • Example: भारत के SPR भंडार। <p>5. Diaspora</p> <ul style="list-style-type: none"> • विदेशों में रहने वाला किसी देश का नागरिक समुदाय। • Example: पश्चिम एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:-1

Geopolitical conflicts in West Asia have far-reaching implications for India's economy and energy security. Discuss.

Keywords: Energy security, oil imports, supply chain disruption, diaspora, financial markets, inflation, diversification, diplomacy

Model Answer Draft

Introduction:

पश्चिम एशिया विश्व के प्रमुख ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और भारत अपनी तेल और गैस की अधिकांश आवश्यकताएँ इसी क्षेत्र से आयात करता है। इसलिए इस क्षेत्र में होने वाले भू-राजनीतिक संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं।

Body:

सबसे पहले, ऊर्जा आपूर्ति पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। युद्ध या राजनीतिक तनाव के कारण तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे भारत जैसे आयातक देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। इससे महंगाई, उत्पादन लागत और व्यापार घाटे में वृद्धि हो सकती है।

दूसरा, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ता है। पश्चिम एशिया उर्वरक और औद्योगिक कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है। इन वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने से कृषि और उद्योग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता भी बढ़ जाती है, जिससे विदेशी निवेश में कमी और मुद्रा पर दबाव देखने को मिलता है।

तीसरा, पश्चिम एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। किसी भी संघर्ष की स्थिति में उनकी सुरक्षा और संभावित निकासी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

Conclusion:

अतः भारत को ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक भंडार का निर्माण और सक्रिय कूटनीति के माध्यम से अपनी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Energy diversification • Strategic reserves • Diaspora safety 	<ul style="list-style-type: none"> • IR answer में economic dimension भूलना • Specific examples न देना

प्रश्न:-2

Discuss the economic and financial consequences of geopolitical conflicts on emerging economies.

Keywords: Financial volatility, capital outflows, currency depreciation, energy prices, trade disruption

Model Answer Draft

Introduction:

भू-राजनीतिक संघर्ष वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को अस्थिर बना देते हैं और इसका प्रभाव विशेष रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है।

Body:

सबसे पहले, ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से आयात लागत बढ़ जाती है, जिससे व्यापार घाटा और महंगाई बढ़ सकती है। दूसरा, वैश्विक निवेशक अनिश्चितता के समय सुरक्षित बाजारों की ओर रुख करते हैं, जिसके कारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी निकासी होती है।

इसके अतिरिक्त, मुद्रा अवमूल्यन और शेयर बाजार में गिरावट भी देखने को मिलती है। यह आर्थिक विकास और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से उद्योगों की उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है।

Conclusion:

इसलिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक लचीलापन बढ़ाने, ऊर्जा विविधीकरण और मजबूत वित्तीय नियामक ढांचे के माध्यम से ऐसे संकटों का सामना करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Capital flow dynamics • Energy price shocks • Policy resilience 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल theoretical discussion • Data/real example न देना

Case Study

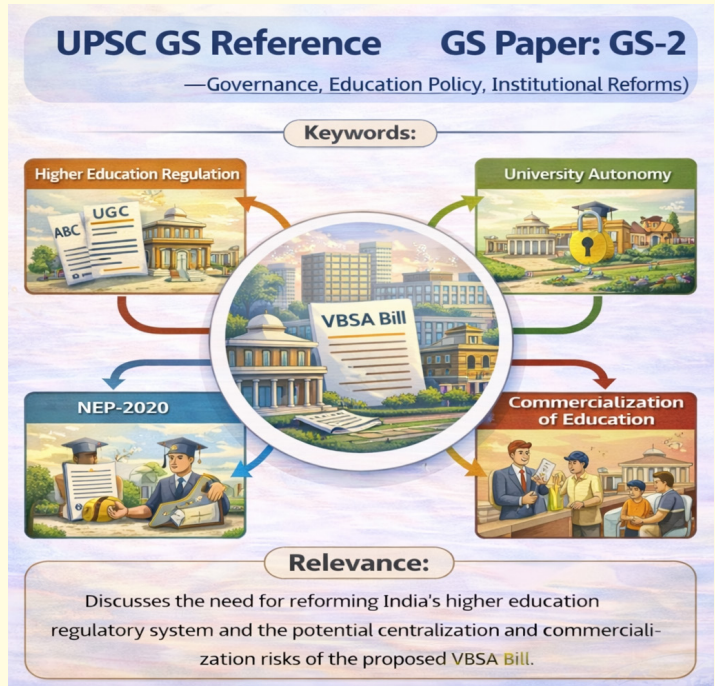
1. Qatar - भारत के LNG आयात का प्रमुख स्रोत
2. BSE Sensex volatility during geopolitical crises
3. Iran-US tensions impacting oil markets

3 UGC needs reform. But the new higher education bill is not the answer

❖ लेख का दृष्टिकोण:

लेखक का तर्क है कि भले ही UGC में सुधार आवश्यक है, लेकिन VBSA Bill उच्च शिक्षा में शक्ति के केंद्रीकरण और राज्य की भूमिका में कमी को बढ़ावा देकर समस्या को और गंभीर बना सकता है।

❖ **Author:** Yogendra Yadav



Article Summary

भूमिका

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से नियामक अक्षमताओं, नौकरशाही हस्तक्षेप और संस्थागत स्वायत्तता की कमी से जूझ रही है। इसी संदर्भ में सरकार ने University Grants Commission को समाप्त कर उसकी जगह एक नई नियामक संरचना बनाने के लिए Viksit Bharat Shiksha Adhishthan (VBSA) Bill प्रस्तावित किया है। यह कदम पहली नजर में सुधार की दिशा में प्रयास प्रतीत होता है, क्योंकि UGC की कार्यप्रणाली पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। किंतु

लेखक का तर्क है कि यह नया विधेयक वास्तव में उच्च शिक्षा में शक्ति के केंद्रीकरण, नौकरशाही नियंत्रण और बाज़ारीकरण को बढ़ावा दे सकता है, जिससे शिक्षा के सार्वजनिक उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

मुख्य भाग

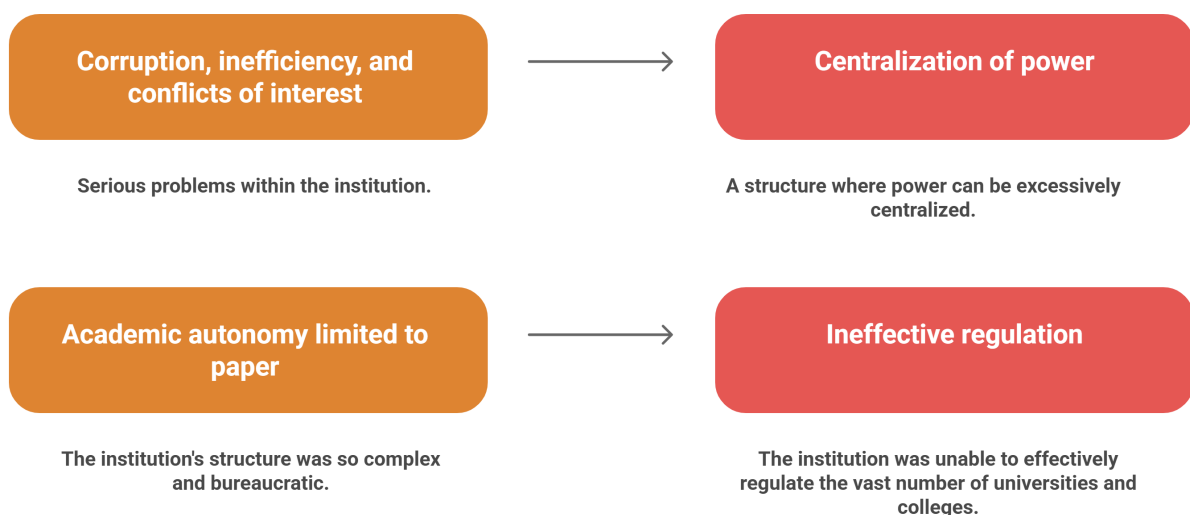
सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि UGC की आलोचना नई नहीं है। लेखक स्वयं UGC के सदस्य रह चुके हैं और उनके अनुभव के अनुसार संस्था में भ्रष्टाचार, अक्षमता और हितों के टकराव जैसी गंभीर समस्याएँ रही हैं। UGC की संरचना इतनी जटिल और नौकरशाही से प्रभावित थी कि वास्तविक शैक्षणिक स्वायत्तता केवल कागज़ों तक सीमित रह गई। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की विशाल संख्या के सामने यह संस्था प्रभावी नियमन करने में असमर्थ रही। यही कारण है कि लंबे समय से उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार की मांग उठती रही है।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सुधार का उद्देश्य केवल पुरानी संस्था को समाप्त करना नहीं बल्कि एक बेहतर और संतुलित नियामक ढाँचा तैयार करना होना चाहिए। National Education Policy 2020 ने भी उच्च शिक्षा में “independent and empowered regulatory bodies” की आवश्यकता पर जोर दिया था, ताकि शक्तियों का संतुलन बना रहे और हितों के टकराव को कम किया जा सके। लेकिन लेखक के अनुसार VBSA Bill इस सिद्धांत के विपरीत जाता है और एक ऐसी संरचना प्रस्तावित करता है जिसमें शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण हो सकता है।

तीसरा पहलू यह है कि उच्च शिक्षा केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में लाखों छात्र ऐसे परिवारों से आते हैं जो पहली बार कॉलेज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा को सार्वजनिक सेवा के रूप में उपलब्ध कराए। यदि नियामक ढाँचा अत्यधिक बाज़ार आधारित हो जाता है, तो शिक्षा महंगी हो सकती है और सामाजिक समानता प्रभावित हो सकती है।

चौथा, लेखक 2009 की Yashpal Committee की सिफारिशों का उल्लेख करते हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय आयोग (NCHER) बनाने का सुझाव दिया गया था। इस मॉडल का उद्देश्य प्रशासनिक नियंत्रण कम करना, अकादमिक स्वायत्तता बढ़ाना और विश्वविद्यालयों को अधिक स्वतंत्रता देना था। इसके विपरीत VBSA Bill केंद्रीकरण और नौकरशाही नियंत्रण को बढ़ाने का खतरा पैदा करता है।

Higher Education Regulation: UGC vs. VBSA Bill



Need for comprehensive reform

A demand for comprehensive reform in higher education has been rising for a long time.

Focus on creating a better regulatory framework

The aim of reform should not be just to abolish the old institution but to create a better and balanced regulatory framework.

Independent and empowered regulatory bodies

National Education Policy 2020 also emphasized the need for "independent and empowered regulatory bodies" in higher education.

Contrary to this principle

According to the author, the VBSA Bill goes against this principle.

Education as a public service

The state has a responsibility to provide education as a public service.

Risk of education becoming expensive

If the regulatory framework becomes excessively market-based, education can become expensive and social equality can be affected.

Reduce administrative control, increase academic autonomy

The Yashpal Committee's model aimed to reduce administrative control, increase academic autonomy, and give more freedom to universities.

Increase centralization and bureaucratic control

The VBSA Bill poses a threat of increasing centralization and bureaucratic control.

निष्कर्ष

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता निर्विवाद है। UGC की सीमाओं और अक्षमताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा नियामक ढाँचा प्रभावी नहीं है। हालांकि, किसी भी सुधार का उद्देश्य संस्थागत स्वायत्तता,

पारदर्शिता और सार्वजनिक हित को मजबूत करना होना चाहिए। यदि नया विधेयक शक्ति के केंद्रीकरण और शिक्षा के बाज़ारीकरण को बढ़ावा देता है, तो यह सुधार के बजाय समस्या को और जटिल बना सकता है। इसलिए नीति निर्माताओं को ऐसा नियामक ढाँचा तैयार करना चाहिए जो विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दे, छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाए और राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करे। लेखक का निष्कर्ष यही है कि सुधार आवश्यक है, परंतु VBSA Bill वर्तमान स्वरूप में इसका सही समाधान नहीं है।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता ● Core claim : VBSA Bill समाधान नहीं है ● Reason-1 : शक्ति का केंद्रीकरण और नौकरशाही नियंत्रण ● Reason-2 : शिक्षा के बाज़ारीकरण का खतरा ● Trade-off : नियमन बनाम स्वायत्तता ● Way forward : संतुलित और स्वतंत्र नियामक संरचना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UGC को लेखक ने "corrupt, inefficient and conflict-ridden system" बताया। 2. 2009 की Yashpal Committee ने UGC और AICTE को समाप्त कर National Commission for Higher Education and Research (NCHER) बनाने की सिफारिश की थी। 3. VBSA Bill को HECI Bill (2018) का पुनरावृत्त रूप बताया गया।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि UGC जैसी अप्रभावी संस्था को समाप्त कर एक नई नियामक संरचना बनाना आवश्यक है ताकि उच्च शिक्षा प्रणाली अधिक कुशल और आधुनिक बन सके। हालांकि लेखक का तर्क है कि यदि नया ढाँचा अत्यधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही नियंत्रण वाला होगा, तो इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षा की सार्वजनिक प्रकृति दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Higher education governance reforms Academic autonomy vs regulatory control 	<ol style="list-style-type: none"> Academic Autonomy <ul style="list-style-type: none"> विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता जिससे वे पाठ्यक्रम और शोध संबंधी निर्णय स्वयं ले सकें। Example: Universities designing their own curriculum. Regulatory Architecture <ul style="list-style-type: none"> किसी क्षेत्र के संचालन और निगरानी के लिए बनाई गई संस्थागत संरचना। Example: UGC regulating higher education.

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Public vs private role in education NEP-2020 regulatory architecture Social equity in higher education Institutional accountability mechanisms 	<p>3. Commercialisation of Education</p> <ul style="list-style-type: none"> शिक्षा को लाभ कमाने वाली गतिविधि के रूप में देखना। Example: Excessive fees in private universities. <p>4. Institutional Reform</p> <ul style="list-style-type: none"> संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार। Example: Replacing outdated regulatory bodies. <p>5. Public Funding</p> <ul style="list-style-type: none"> सरकार द्वारा शिक्षा या अन्य सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता। Example: Government grants to universities.

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

Discuss the challenges in India's higher education regulatory framework and evaluate the need for institutional reforms.

Keywords: UGC, autonomy, regulation, NEP-2020, governance, accountability, commercialization

Model Answer Draft

Introduction:

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें हजारों विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं। इस विशाल प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक मजबूत और संतुलित नियामक ढाँचा आवश्यक है।

Body:

वर्तमान प्रणाली में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं। सबसे पहले, नियामक संस्थाओं की बहुलता और नौकरशाही नियंत्रण विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सीमित करते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार और हितों के टकराव जैसी समस्याएँ संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। तीसरा, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक अक्षमता के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। सुधार का उद्देश्य नियमन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना होना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों को अकादमिक स्वतंत्रता और नवाचार के लिए पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना भी आवश्यक है।

Conclusion:

इस प्रकार उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार केवल संस्थाओं को बदलने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा संतुलित ढाँचा विकसित करना चाहिए जो गुणवत्ता, स्वायत्तता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सके।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Institutional reform framework • Autonomy + accountability balance • Public funding importance 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल UGC criticism लिखना • policy alternatives न देना

प्रश्न:-2

Examine the role of the state in ensuring equitable access to higher education in India.

Keywords: Public funding, social equity, first-generation learners, inclusion, education policy

Model Answer Draft

Introduction:

उच्च शिक्षा सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में राज्य की भूमिका शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Body:

राज्य की भूमिका कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, छात्रवृत्ति, आरक्षण और वित्तीय सहायता योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को समर्थन देना। तीसरा, शिक्षा के बाज़ारीकरण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नियामक ढाँचा तैयार करना।

इसके अतिरिक्त राज्य को अनुसंधान और नवाचार के लिए निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बन सकें। यदि शिक्षा पूरी तरह बाजार शक्तियों पर निर्भर हो जाए तो गरीब और वंचित वर्गों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो सकता है।

Conclusion:

इसलिए राज्य को एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए ऐसा संतुलित मॉडल विकसित करना चाहिए जिसमें सार्वजनिक निवेश, प्रभावी नियमन और सामाजिक समावेशन तीनों सुनिश्चित हों।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • Social justice dimension • Public investment argument • Inclusive education policies 	<ul style="list-style-type: none"> • Equity dimension भूल जाना • real policy references न देना

Case Study

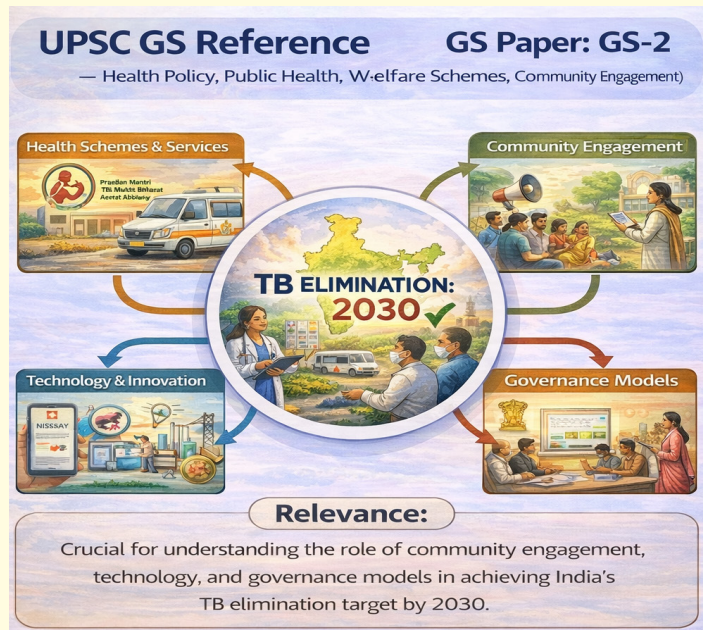
1. University Grants Commission reforms debate
2. National Education Policy 2020
3. Yashpal Committee recommendations (2009)

4 Science and the power of jan bhagidari can lead to a TB-free India

❖ लेख का दृष्टिकोण:

भारत में विज्ञान, नीति-समर्थित स्वास्थ्य प्रणाली और जनभागीदारी के संयुक्त प्रयास से टीबी-मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

❖ Author: Jagat Prakash Nadda



Article Summary

भूमिका

भारत विश्व में टीबी (Tuberculosis) के सर्वाधिक बोझ वाले देशों में रहा है, लेकिन पिछले दशक में इसके उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। भारत ने वैश्विक लक्ष्य 2035 की तुलना में 2030 तक टीबी उन्मूलन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। लेख के अनुसार, यह लक्ष्य केवल सरकारी कार्यक्रमों से संभव नहीं होगा; इसके लिए वैज्ञानिक नवाचार, स्वास्थ्य अवसंरचना और समाज की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। "टीबी मुक्त भारत अभियान" और 100-दिवसीय अभियान जैसे प्रयास बताते हैं कि जब नागरिक, समुदाय, स्वास्थ्यकर्मी

और सरकार एक साथ कार्य करते हैं, तब सार्वजनिक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियों से निपटना संभव हो जाता है।

मुख्य भाग

(1) भारत में टीबी की चुनौती और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

टीबी भारत के लिए केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक चुनौती भी है। यह बीमारी मुख्यतः गरीब और कमजोर वर्गों को प्रभावित करती है, जिससे उनकी उत्पादकता घटती है और परिवार आर्थिक संकट में फँस जाता है।

भारत में हर वर्ष लाखों लोग टीबी से प्रभावित होते हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव पड़ता है। इसके अलावा टीबी के साथ सामाजिक कलंक (stigma) जुड़ा होने के कारण कई मरीज उपचार लेने से हिचकते हैं। यह कलंक बीमारी के नियंत्रण में एक बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए केवल चिकित्सा उपचार पर्याप्त नहीं है; सामाजिक जागरूकता और समुदाय आधारित समर्थन भी उतना ही आवश्यक है।

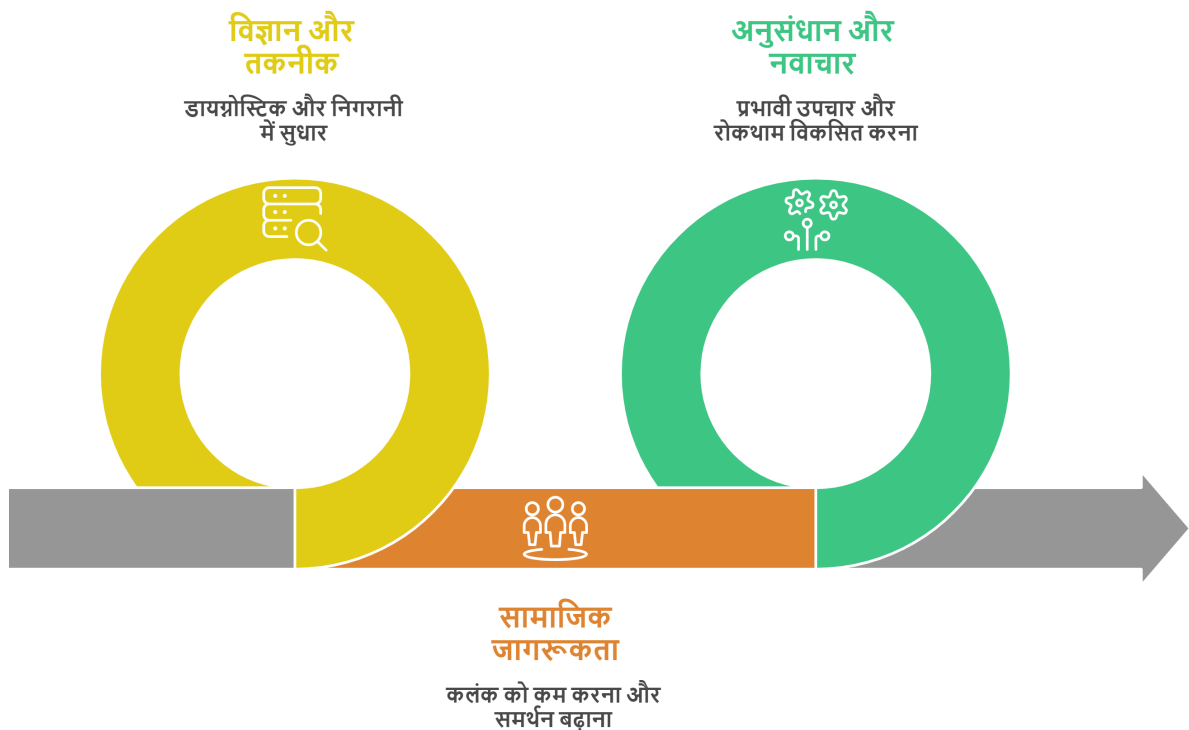
(2) विज्ञान और तकनीक की भूमिका

लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत ने टीबी से लड़ने में विज्ञान और तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है। आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों, डिजिटल निगरानी प्रणाली और दवा वितरण तंत्र ने बीमारी की पहचान और उपचार को तेज किया है।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में नए परीक्षण उपकरण, उन्नत दवाएँ और डेटा-आधारित निगरानी प्रणाली शामिल हैं। इससे रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार संभव हुआ है।

इसके अतिरिक्त, टीबी नियंत्रण कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और नवाचार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि भविष्य में अधिक प्रभावी उपचार और रोकथाम के उपाय विकसित किए जा सकें।

भारत में टीबी को हराना



(3) जनभागीदारी (Jan Bhagidari) का महत्व

लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज-व्यापी आंदोलन होना चाहिए।

“जन भागीदारी” का अर्थ है कि नागरिक, सामाजिक संगठन, निजी क्षेत्र और समुदाय सभी मिलकर इस अभियान में योगदान दें।

उदाहरण के लिए, कई स्थानों पर स्वयंसेवक, सामाजिक संगठन और स्थानीय समुदाय टीबी मरीजों की सहायता, पोषण समर्थन और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसी प्रकार, Mission Indradhanush जैसे स्वास्थ्य अभियानों की सफलता ने यह दिखाया है कि जब समुदाय सक्रिय रूप से शामिल होता है तो बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सुधार संभव होते हैं।

टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी का महत्व



(4) टीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक सामाजिक परिवर्तन

लेख यह भी रेखांकित करता है कि टीबी उन्मूलन के लिए केवल चिकित्सा उपचार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन भी आवश्यक हैं। समाज को टीबी के प्रति जुड़े भेदभाव और कलंक को समाप्त करना होगा।

इसके साथ ही नागरिकों को स्वास्थ्य-अनुकूल जीवनशैली, स्वच्छता और समय पर उपचार को अपनाना होगा।

यदि समाज के सभी वर्ग — सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक और संस्थाएँ — मिलकर कार्य करें तो भारत टीबी-मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

टीबी उन्मूलन भारत के लिए केवल एक स्वास्थ्य लक्ष्य नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और मानव विकास का प्रश्न भी है। इस दिशा में विज्ञान, नीति-निर्माण और जनभागीदारी का संयोजन निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

भारत का अनुभव यह दर्शाता है कि जब समाज सामूहिक रूप से किसी लक्ष्य के लिए कार्य करता है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है।

लेख का संदेश स्पष्ट है कि टीबी-मुक्त भारत केवल सरकारी कार्यक्रमों से नहीं बल्कि नागरिकों के व्यवहार, समुदाय के सहयोग और सामाजिक संवेदनशीलता से निर्मित होगा। यदि कलंक को समाप्त किया जाए और उपचार तक पहुँच सुनिश्चित की जाए, तो भारत 2030 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> • Context : भारत में टीबी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती • Core claim : विज्ञान + जनभागीदारी से टीबी उन्मूलन संभव 	<ol style="list-style-type: none"> 1. भारत में टीबी मुक्त भारत अभियान — 100 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> • Reason-1 : तकनीकी नवाचार और स्वास्थ्य अवसंरचना • Reason-2 : समुदाय की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता • Trade-off : सामाजिक कलंक और उपचार तक सीमित पहुँच • Way forward : whole-of-society approach + वैज्ञानिक रणनीति 	<ol style="list-style-type: none"> 2. भारत की टीबी रणनीति जनभागीदारी आधारित whole-of-society approach पर आधारित है। 3. Mission Indradhanush जैसे कार्यक्रमों की सफलता ने समुदाय आधारित स्वास्थ्य अभियानों की प्रभावशीलता सिद्ध की।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी है क्योंकि स्वास्थ्य अवसंरचना, पोषण की कमी और सामाजिक असमानताएँ अभी भी बड़ी बाधाएँ हैं। हालांकि, लेख का तर्क है कि यदि वैज्ञानिक तकनीक, मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और जनभागीदारी को एकीकृत किया जाए, तो इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है और लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति संभव है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> WHO Global TB Strategy — वैश्विक स्तर पर टीबी उन्मूलन का ढाँचा भारत का लक्ष्य: 2030 तक TB elimination Whole-of-society approach सार्वजनिक स्वास्थ्य में Behavioural change communication (BCC) 	<ol style="list-style-type: none"> Tuberculosis (टीबी) <ul style="list-style-type: none"> एक संक्रामक रोग जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। उदाहरण: भारत में लाखों लोग प्रतिवर्ष टीबी से प्रभावित होते हैं। Jan Bhagidari (जनभागीदारी) <ul style="list-style-type: none"> सरकारी कार्यक्रमों में नागरिकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी। उदाहरण: टीबी उन्मूलन अभियान में स्वयंसेवकों का योगदान। Public Health Campaign <ul style="list-style-type: none"> किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के नियंत्रण के लिए व्यापक सामाजिक अभियान। उदाहरण: टीबी मुक्त भारत अभियान। Stigma (सामाजिक कलंक) <ul style="list-style-type: none"> किसी बीमारी या स्थिति के कारण समाज द्वारा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। उदाहरण: टीबी मरीजों के प्रति सामाजिक भेदभाव।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Digital health surveillance systems Public health governance + community participation 	<p>5. Preventive Healthcare</p> <ul style="list-style-type: none"> बीमारी के होने से पहले ही उसे रोकने के उपाय। उदाहरण: टीबी के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता और नियमित जांच।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

“भारत में टीबी उन्मूलन के लिए जनभागीदारी और वैज्ञानिक नवाचार की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।” (15 marks)

Keywords: TB elimination, public health governance, jan bhagidari, community participation, digital health, stigma reduction, preventive healthcare, WHO targets

Model Answer Draft

Introduction:

टीबी विश्व की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में से एक है और भारत इसका सबसे बड़ा बोझ वहन करता है। भारत ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे प्राप्त करने के लिए विज्ञान, नीति और जनभागीदारी का समन्वित प्रयास आवश्यक है।

Body:

पहला, वैज्ञानिक नवाचार टीबी नियंत्रण का महत्वपूर्ण आधार है। आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीक, डिजिटल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली और उन्नत दवाओं ने रोग की शीघ्र पहचान और उपचार को संभव बनाया है।

दूसरा, स्वास्थ्य प्रशासन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा-आधारित निगरानी के माध्यम से मरीजों की पहचान और उपचार की निरंतरता सुनिश्चित की है।

तीसरा, जनभागीदारी (Jan Bhagidari) ने इस अभियान को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया है। स्वयंसेवी संगठन, समुदाय और नागरिक टीबी मरीजों को पोषण सहायता, जागरूकता और उपचार समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

चौथा, सामाजिक कलंक को समाप्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि टीबी के साथ जुड़े भेदभाव के कारण कई मरीज उपचार लेने से बचते हैं।

Conclusion:

इस प्रकार, टीबी उन्मूलन केवल चिकित्सा कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक, तकनीकी और प्रशासनिक प्रयासों का संयुक्त परिणाम है। यदि विज्ञान और जनभागीदारी का यह मॉडल निरंतर सुदृढ़ किया जाए, तो भारत टीबी-मुक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकता है।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> • WHO TB elimination target • Community-based health model • Digital health governance 	<ul style="list-style-type: none"> • केवल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का वर्णन करना • जनभागीदारी के सामाजिक पहलू को न जोड़ना

प्रश्न:-2

“सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों की सफलता में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।” (15 marks)

Keywords: behaviour change, public health campaigns, stigma, community awareness, preventive healthcare, health governance, social participation, policy implementation

Model Answer Draft

Introduction:

सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों की सफलता केवल चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समाज के व्यवहार, जागरूकता और सहभागिता पर भी निर्भर करती है। टीबी उन्मूलन अभियान इसका प्रमुख उदाहरण है।

Body:

पहला, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन से रोग की रोकथाम संभव होती है। स्वच्छता, पोषण और समय पर उपचार जैसे व्यवहार टीबी जैसी बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं।

दूसरा, जागरूकता अभियानों से लोगों में बीमारी के प्रति समझ बढ़ती है और वे समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं।

तीसरा, सामाजिक कलंक को समाप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीबी के साथ जुड़ा भेदभाव कई रोगियों को उपचार से दूर रखता है, जिससे बीमारी का प्रसार बढ़ता है।

चौथा, सामुदायिक संगठनों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी स्वास्थ्य अभियानों को व्यापक और प्रभावी बनाती है।

Conclusion:

अतः सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों की सफलता के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, जनभागीदारी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक हैं। जब समाज स्वयं स्वास्थ्य सुधार के प्रयासों में सहभागी बनता है, तब स्वास्थ्य नीतियाँ अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनती हैं।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Behavioural change communication ● Community participation ● Preventive health model 	<ul style="list-style-type: none"> ● केवल चिकित्सा दृष्टिकोण पर ध्यान देना ● सामाजिक पहलुओं को न जोड़ना

Case Study

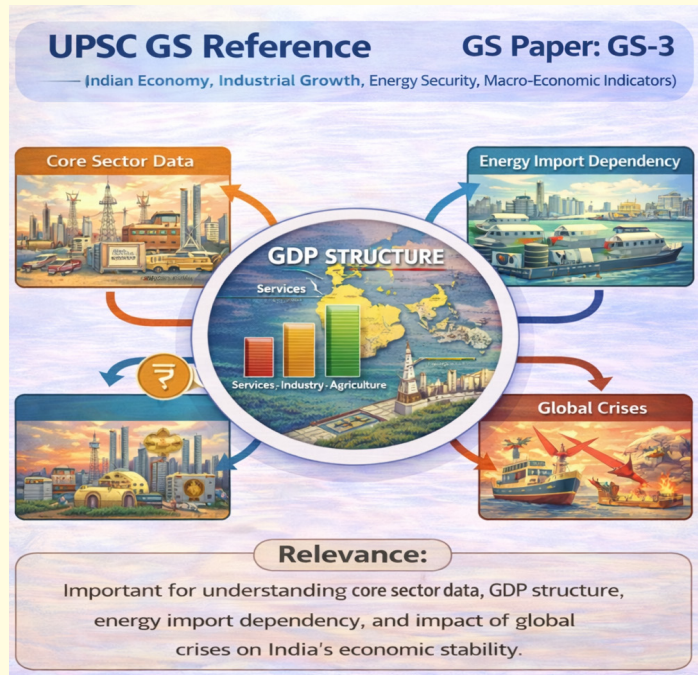
1. **TB Mukht Bharat Abhiyaan (100-day campaign)** - सामुदायिक भागीदारी आधारित मॉडल
2. **Mission Indradhanush** - टीकाकरण कार्यक्रम में जनभागीदारी की सफलता
3. **Nikshay पोर्टल** - टीबी मरीजों की डिजिटल ट्रैकिंग और उपचार निगरानी

5 Grim future: On the economy, discomfiting data

❖ लेख का दृष्टिकोण:

भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर प्रचलित धारणा के बावजूद, हालिया आर्थिक संकेतक बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन आवश्यक है।

❖ **Author:** Editorial



Article Summary

भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक आधारों और उच्च विकास दर के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हाल के आर्थिक आँकड़े इस धारणा को चुनौती देते हुए कुछ चिंताजनक संकेत दे रहे हैं। फरवरी 2026 के कोर सेक्टर इंडेक्स (Index of Eight Core Industries) के आँकड़ों में वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही तेल और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लंबे समय से संकुचन देखा जा रहा है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है, यह स्थिति भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता और आर्थिक संरचना की कमजोरियों को उजागर करती है।

मुख्य भाग

(1) कोर सेक्टर के आँकड़ों से उभरती आर्थिक चुनौतियाँ

भारत की औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण संकेतक कोर सेक्टर इंडेक्स है, जिसमें आठ प्रमुख उद्योग शामिल हैं जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली।

फरवरी 2026 के आँकड़ों में इस सूचकांक की वृद्धि दर घटकर तीन महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई। यह गिरावट किसी उच्च आधार प्रभाव के कारण नहीं थी, क्योंकि फरवरी 2025 में भी वृद्धि केवल 3.4% थी।

क्षेत्रीय आँकड़ों से पता चलता है कि घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में पिछले छह महीनों से लगातार गिरावट आ रही है और पिछले 24 महीनों में से 20 महीनों में यह क्षेत्र संकुचित हुआ है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस उत्पादन में भी लगातार 20 महीनों से गिरावट देखी जा रही है।

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों में गंभीर संरचनात्मक समस्याएँ मौजूद हैं।

(2) ऊर्जा आयात निर्भरता और रणनीतिक दूरदर्शिता की कमी

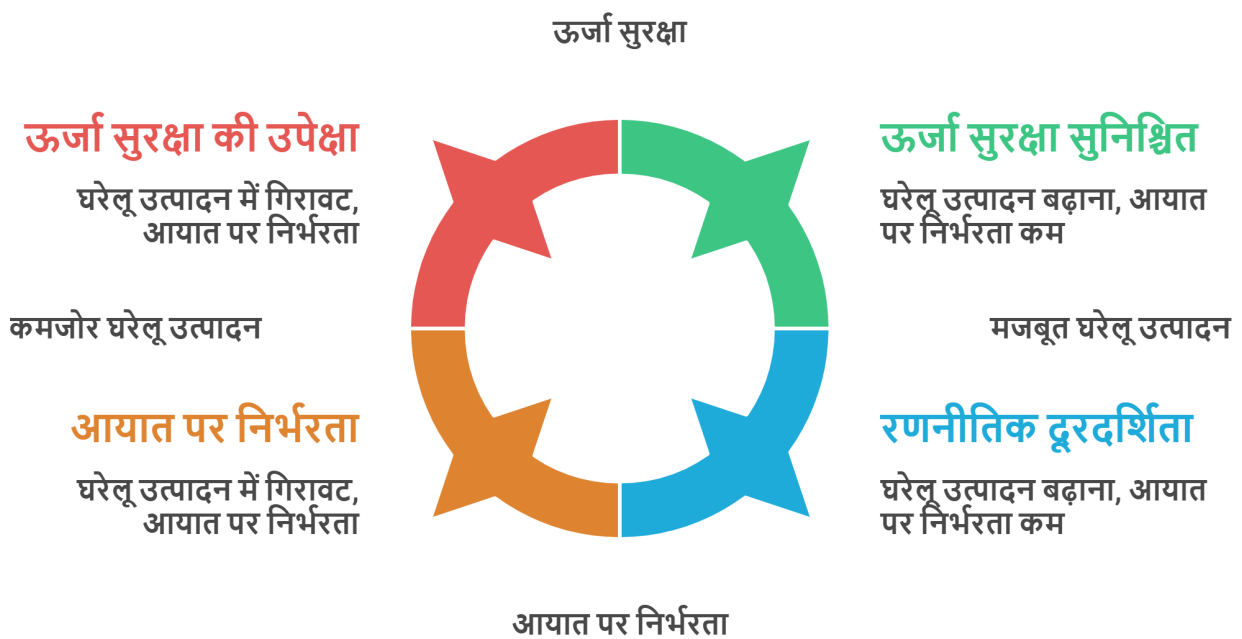
भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है, विशेषकर पश्चिम एशिया से।

जब अमेरिका-ईरान तनाव पिछले वर्ष से बढ़ रहा था, तब यह अनुमान लगाया जा सकता था कि ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाकर भंडार तैयार करना एक रणनीतिक कदम हो सकता था।

हालाँकि सस्ता आयात उपलब्ध होने के कारण घरेलू उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप वर्तमान संकट के समय भारत को ऊर्जा आपूर्ति संकट का सामना करना पड़ रहा है।

यह स्थिति दर्शाती है कि ऊर्जा नीति में दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और ऊर्जा सुरक्षा को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है।

आर्थिक चुनौतियाँ और रणनीतिक समाधान



(3) GDP संरचना और मांग की कमजोरी

हालिया GDP आँकड़ों से भी कुछ चिंताजनक प्रवृत्तियाँ सामने आई हैं। नई श्रृंखला के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पहले के अनुमान से छोटा है।

इसके अतिरिक्त 2022-23 से 2025-26 के बीच GDP में निजी उपभोग, निवेश (capital formation), निर्यात और आयात जैसे प्रमुख विकास इंजनों का योगदान घट गया है।

इसके विपरीत 'change in stocks' का हिस्सा लगभग दोगुना हो गया है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन तो हो रहा है लेकिन बाजार में पर्याप्त बिक्री नहीं हो रही। यदि मांग कमजोर बनी रहती है तो उद्योग धीरे-धीरे उत्पादन कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

(4) वैश्विक संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर कर रहा है। तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक पहुँच चुकी हैं। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में कई अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों ने भारत की विकास दर के अनुमान को लगभग 6.5% तक घटा दिया है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर जो धारणा बनाई जाती है, उसका यथार्थवादी पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि



निष्कर्ष

हालिया आर्थिक आँकड़े यह संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कई संरचनात्मक चुनौतियाँ मौजूद हैं। कोर सेक्टर की धीमी वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन में गिरावट और कमजोर मांग जैसे कारक भविष्य की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के कारण ऊर्जा कीमतों और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है।

ऐसे में नीति-निर्माताओं को ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू उत्पादन वृद्धि, मांग सुदृढीकरण और आर्थिक संरचनात्मक सुधारों पर अधिक ध्यान देना होगा। लेखक का निष्कर्ष है कि भारत की आर्थिक मजबूती के दावों के बजाय वास्तविक चुनौतियों को स्वीकार कर व्यावहारिक नीतियाँ बनाना अधिक आवश्यक है।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : हालिया आर्थिक आँकड़े चिंताजनक संकेत दे रहे हैं ● Core claim : भारत की आर्थिक मजबूती का यथार्थवादी पुनर्मूल्यांकन आवश्यक ● Reason-1 : कोर सेक्टर वृद्धि में गिरावट ● Reason-2 : ऊर्जा उत्पादन में गिरावट और आयात निर्भरता 	<ol style="list-style-type: none"> 1. फरवरी 2026 में Index of Eight Core Industries की वृद्धि दर तीन महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई। 2. घरेलू कच्चे तेल क्षेत्र पिछले 24 महीनों में से 20 महीनों में संकुचित हुआ।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> • Trade-off : कमजोर मांग और उत्पादन-भंडार असंतुलन • Way forward : ऊर्जा सुरक्षा + आर्थिक संरचनात्मक सुधार 	<p>3. वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक पहुँच गईं।</p>

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ अर्थशास्त्री यह तर्क देते हैं कि भारत अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अस्थायी उतार-चढ़ाव दीर्घकालिक प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करेंगे। हालांकि लेख का तर्क है कि कोर सेक्टर में लगातार गिरावट, ऊर्जा निर्भरता और मांग की कमजोरी जैसे संकेतकों को नज़रअंदाज़ करना जोखिमपूर्ण हो सकता है और नीति-निर्माताओं को इन संकेतों के आधार पर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> • Index of Eight Core Industries — औद्योगिक गतिविधि का प्रमुख संकेतक 	<p>1. Core Sector</p> <ul style="list-style-type: none"> • अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख उद्योग जो औद्योगिक उत्पादन की आधारशिला हैं। • उदाहरण: कोयला, कच्चा तेल और इस्पात।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> ● Energy security — ऊर्जा आयात निर्भरता कम करना ● Demand-supply imbalance ● Macroeconomic fundamentals ● Strategic petroleum reserves ● Global oil price volatility 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Energy Security <ul style="list-style-type: none"> ● किसी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता। ● उदाहरण: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। 3. Macroeconomic Fundamentals <ul style="list-style-type: none"> ● अर्थव्यवस्था के मूल संकेतक जैसे GDP, मुद्रास्फीति, निवेश और रोजगार। ● उदाहरण: उच्च विकास दर और नियंत्रित मुद्रास्फीति 4. Change in Stocks <ul style="list-style-type: none"> ● GDP में वह घटक जो उत्पादन और बिक्री के बीच के अंतर को दर्शाता है। ● उदाहरण: उत्पादन अधिक लेकिन बिक्री कम होने पर भंडार बढ़ जाता है। 5. Oil Price Shock <ul style="list-style-type: none"> ● तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। ● उदाहरण: 1973 का तेल संकट।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

“कोर सेक्टर के प्रदर्शन में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत देती है? विश्लेषण कीजिए।” (15 marks)

Keywords: core industries, industrial growth, energy security, demand slowdown, macroeconomic indicators, production trends, economic resilience

Model Answer Draft

Introduction:

कोर सेक्टर भारतीय औद्योगिक उत्पादन का आधार है और इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और बिजली जैसे आठ प्रमुख उद्योग शामिल हैं। इन क्षेत्रों का प्रदर्शन समग्र आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण संकेतक होता है।

Body:

हालिया आँकड़ों के अनुसार कोर सेक्टर की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है।

पहला, ऊर्जा क्षेत्रों — विशेषकर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस — में लंबे समय से संकुचन देखने को मिला है, जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

दूसरा, ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के समय आर्थिक जोखिम बढ़ाती है।

तीसरा, उत्पादन और मांग के बीच असंतुलन भी उभरकर सामने आया है। 'Change in stocks' का बढ़ता हिस्सा संकेत देता है कि उत्पादन तो हो रहा है लेकिन बाजार में मांग पर्याप्त नहीं है।

चौथा, यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो निवेश, रोजगार और आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

Conclusion:

अतः कोर सेक्टर के प्रदर्शन में गिरावट केवल औद्योगिक समस्या नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक चुनौती का संकेत है। इसे दूर करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा, मांग प्रोत्साहन और औद्योगिक नीति सुधारों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Core industries importance ● Energy dependency issue ● Demand-supply imbalance 	<ul style="list-style-type: none"> ● कोर सेक्टर की सूची का उल्लेख न करना ● ऊर्जा सुरक्षा को उत्तर से बाहर रखना

प्रश्न:-2

“ऊर्जा आयात निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार जोखिम उत्पन्न करती है?” (15 marks)

Keywords: energy imports, oil dependency, geopolitical risk, energy security, strategic reserves, economic stability

Model Answer Draft

Introduction:

भारत विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है और अपनी तेल एवं गैस आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यह स्थिति आर्थिक स्थिरता के लिए कई प्रकार के जोखिम उत्पन्न करती है।

Body:

पहला, ऊर्जा आयात निर्भरता वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अर्थव्यवस्था को संवेदनशील बनाती है। तेल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति और चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है।

दूसरा, भू-राजनीतिक संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में संघर्ष, ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं।

तीसरा, आयात पर अधिक निर्भरता से घरेलू ऊर्जा उत्पादन और अनुसंधान को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता।

चौथा, ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है।

Conclusion:

इसलिए भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और रणनीतिक भंडार विकसित करने जैसे कदम महत्वपूर्ण होंगे।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> ● Oil price shocks ● Energy security strategy ● Strategic reserves 	<ul style="list-style-type: none"> ● केवल तेल पर ध्यान देना, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों को नजरअंदाज करना ● वैश्विक भू-राजनीतिक संदर्भ को शामिल न करना

Case Study

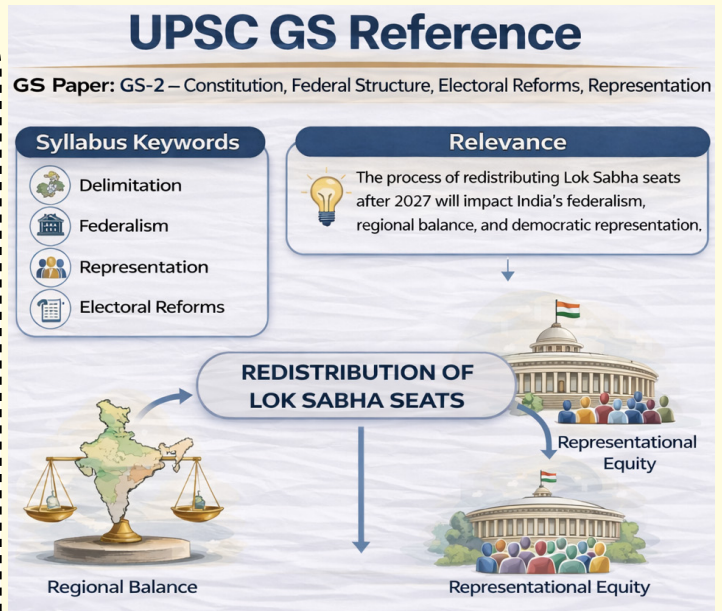
1. भारत की Strategic Petroleum Reserves (SPR) नीति
2. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (2016) — LPG मांग और ऊर्जा नीति का संबंध
3. वैश्विक Oil price shocks (1973, 2008) का आर्थिक प्रभाव

6 Delimitation after 2027, redrawing power in India

❖ लेख का दृष्टिकोण:

यदि 2027 के बाद होने वाला परिसीमन (Delimitation) केवल राजनीतिक गणित पर आधारित हुआ, तो यह भारत के संघवाद और क्षेत्रीय संतुलन को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।

❖ **Author: S.Y. Quraishi**



Article Summary

भूमिका

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनसंख्या परिवर्तन के अनुसार चुनावी क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण आवश्यक होता है, जिसे परिसीमन (Delimitation) कहा जाता है। भारत में यह प्रक्रिया संविधान के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद की जानी थी, लेकिन 1976 से राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण स्थगित है। इसका उद्देश्य उन राज्यों को दंडित होने से बचाना था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई। अब 2027 की जनगणना के बाद होने वाला परिसीमन भारत की राजनीति और संघीय संरचना को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यह केवल सीटों का पुनर्वितरण नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति के नए संतुलन को निर्धारित करेगा।

मुख्य भाग

(1) परिसीमन की संवैधानिक व्यवस्था

भारत के संविधान में चुनावी प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के अनुपात में बनाए रखने के लिए परिसीमन का प्रावधान किया गया है।

इसके लिए समय-समय पर Delimitation Commission का गठन किया जाता है, जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ और सीटों का वितरण तय करता है।

हालाँकि 1976 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थगित कर दिया गया था।

इसका उद्देश्य यह था कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, उन्हें कम जनसंख्या वृद्धि के कारण संसद में कम प्रतिनिधित्व न मिले।

(2) 84वाँ संविधान संशोधन और 2027 के बाद की स्थिति

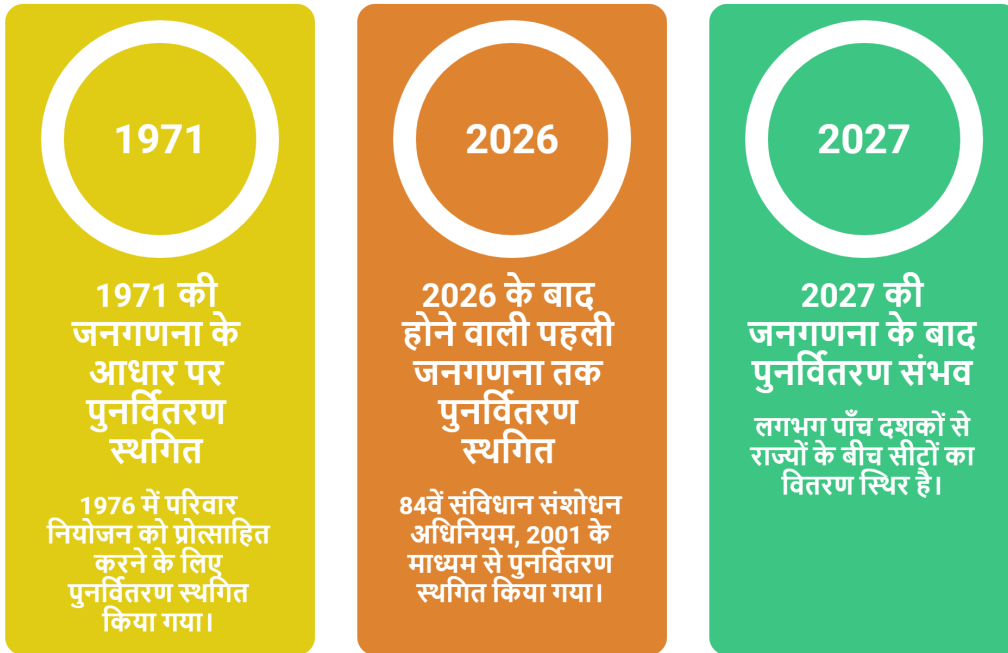
2001 में हुए Eighty-fourth Constitutional Amendment Act, 2001 के माध्यम से राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थगित कर दिया गया।

इसका अर्थ है कि 2027 की जनगणना के बाद भारत में लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण संभव होगा।

यह परिसीमन प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पिछले लगभग पाँच दशकों से राज्यों के बीच सीटों का वितरण स्थिर बना हुआ है।

नई जनसंख्या संरचना के आधार पर कई राज्यों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि या कमी हो सकती है।

परिसीमन की संवैधानिक व्यवस्था और 2027 के बाद की स्थिति



परिसीमन की संवैधानिक व्यवस्था जनसंख्या के अनुपात में चुनावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, लेकिन 2027 तक पुनर्वितरण स्थगित कर दिया गया है।

(3) संघवाद और क्षेत्रीय संतुलन की चुनौती

भारत के संघीय ढाँचे में राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अधिक लोकसभा सीटें मिल सकती हैं।

इसके विपरीत जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

यह स्थिति दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच राजनीतिक असंतुलन को बढ़ा सकती है और संघीय संरचना में तनाव पैदा कर सकती है।

इसलिए परिसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन और प्रशासनिक प्रभावशीलता जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(4) राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रभाव

परिसीमन केवल चुनावी क्षेत्रों की सीमाएँ तय करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

यदि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित नहीं किया गया, तो यह राजनीतिक विवाद और क्षेत्रीय असंतोष को जन्म दे सकती है।

इसलिए आवश्यक है कि परिसीमन को स्वतंत्र आयोग, पारदर्शी मानकों और व्यापक राजनीतिक सहमति के आधार पर संचालित किया जाए।

परिसीमन प्रक्रिया का परिवर्तन



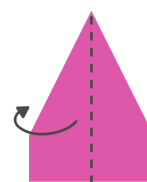
**जनसंख्या-
आधारित
परिसीमन**
केवल जनसंख्या के
आधार पर सीटें
आवंटित



क्षेत्रीय संतुलन
जनसंख्या के साथ
क्षेत्रीय संतुलन पर
विचार



**प्रशासनिक
प्रभावशीलता**
प्रशासनिक
प्रभावशीलता को ध्यान
में रखना



पारदर्शी प्रक्रिया
स्वतंत्र आयोग और
पारदर्शी मानक



**निष्पक्ष
परिसीमन**
संतुलित और निष्पक्ष
प्रतिनिधित्व

निष्कर्ष

2027 के बाद होने वाला परिसीमन भारत की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह प्रक्रिया केवल लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि भारत में राजनीतिक शक्ति के नए संतुलन को निर्धारित करेगी।

यदि इसे केवल जनसंख्या आधारित गणित या राजनीतिक हितों के आधार पर किया गया, तो यह क्षेत्रीय असंतोष और संघीय तनाव को बढ़ा सकता है।

इसलिए परिसीमन प्रक्रिया को न्यायसंगत, पारदर्शी और संघीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए संचालित करना आवश्यक है। तभी यह भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय विभाजन का कारण बनने से बच सकेगी।

Article Draft	मुख्य विचार
<ul style="list-style-type: none"> ● Context : लोकतंत्र में समय-समय पर परिसीमन आवश्यक ● Core claim : 2027 के बाद का परिसीमन भारत की राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदल देगा ● Reason-1 : 1976 से सीटों का वितरण स्थिर ● Reason-2 : जनसंख्या परिवर्तन के कारण प्रतिनिधित्व असंतुलन ● Trade-off : जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व बनाम संघीय संतुलन ● Way forward : निष्पक्ष आयोग + राष्ट्रीय सहमति 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1976 से राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का वितरण 1971 की जनगणना पर स्थिर है। 2. 84वाँ संविधान संशोधन (2001) — सीट पुनर्वितरण को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थगित किया गया। 3. 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन भारत में राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदल सकता है।

लेखक के दृष्टिकोण के विपक्ष में तर्क

कुछ लोग तर्क देते हैं कि लोकतंत्र में "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत सर्वोपरि होना चाहिए, इसलिए परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। लेकिन लेखक का मानना है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण संघीय देश में केवल जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण से क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

लेख के अन्य परीक्षा उपयोगी संदर्भ

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> ● Delimitation Commission — स्वतंत्र संवैधानिक निकाय ● One person, one vote principle ● Federal balance in representation 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delimitation <ul style="list-style-type: none"> ● निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। ● उदाहरण: जनगणना के बाद परिसीमन। 2. Federalism (संघवाद) <ul style="list-style-type: none"> ● शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ● उदाहरण: भारत का संघीय ढाँचा। 3. Representation <ul style="list-style-type: none"> ● संसद या विधानसभाओं में नागरिकों का प्रतिनिधित्व। ● उदाहरण: लोकसभा सीटों का वितरण।

UPSC Value Addition	Prelims Special
<ul style="list-style-type: none"> Population control policy impact Regional political representation Electoral reforms debate 	<p>4. Census (जनगणना)</p> <ul style="list-style-type: none"> जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया। उदाहरण: 2027 की संभावित जनगणना। <p>5. Electoral Reforms</p> <ul style="list-style-type: none"> चुनावी प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के सुधार। उदाहरण: परिसीमन आयोग का गठन।

Practice Questions (Mains)

प्रश्न:- 1

“भारत में 2027 के बाद होने वाला परिसीमन संघीय ढाँचे और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है?” (15 marks)

Keywords: delimitation, federalism, representation, population growth, electoral reform, regional balance

Model Answer Draft

Introduction:

परिसीमन लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया है। भारत में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण 1976 से स्थगित है।

Body:

2027 की जनगणना के बाद परिसीमन होने की संभावना है, जिससे कई महत्वपूर्ण प्रभाव सामने आ सकते हैं।

पहला, जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, जिससे संसद में उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी।

दूसरा, जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है, उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।

तीसरा, इससे क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक तनाव की संभावना बढ़ सकती है।

चौथा, परिसीमन प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अधिक समान बनाने में भी सहायक हो सकती है।

Conclusion:

अतः परिसीमन को संतुलित दृष्टिकोण से लागू करना आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन दोनों सुरक्षित रह सकें।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> Federal balance Population vs representation Electoral reforms 	<ul style="list-style-type: none"> परिसीमन और निर्वाचन सुधारों में भ्रम संघवाद के पहलू को उत्तर में शामिल न करना

प्रश्न:-2

“परिसीमन प्रक्रिया भारत में ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ सिद्धांत और संघीय संतुलन के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकती है?” (15 marks)

Keywords: electoral justice, federal balance, representation, population control, delimitation commission

Model Answer Draft

Introduction:

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक नागरिक का वोट समान मूल्य रखे। परिसीमन प्रक्रिया इसी सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करती है।

Body:

पहला, परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारित करता है।

दूसरा, इससे प्रतिनिधित्व अधिक समान और न्यायसंगत बनता है।

हालाँकि भारत जैसे संघीय देश में केवल जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व से क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।

इसलिए परिसीमन में संघीय संतुलन, प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय हितों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

Conclusion:

अतः परिसीमन को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक समानता और संघीय संतुलन दोनों सुरक्षित रहें, जिससे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हो सके।

High-Scoring Cues	Mistakes
<ul style="list-style-type: none"> One person one vote Federal equilibrium Balanced representation 	<ul style="list-style-type: none"> केवल जनसंख्या पहलू पर ध्यान देना संघीय संरचना को नजरअंदाज करना

Case Study

- 1976 Delimitation freeze - जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने का प्रयास
- 2002 Delimitation Commission - निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण
- दक्षिण बनाम उत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व विवाद



NEW BATCH

General Studies

IAS/PCS

(Hindi Medium)





30th MARCH 2026

8:30 am



OPEN TO ALL FOR 3 DAYS

 S.P Marg, Civil Lines, Prayagraj

 **8853467068**